RAJYA SABHA

Monday, the 8th May, 1989/18th Vaisakha, 1911 (Saka)

The House met eleven of the clock. Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Pending applications for telephone connections in towns of Gujarat

*181. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of applications pending for new telephone connections in Ahmedabad, Baroda, Rajkot and Surat as on 31st March, 1989;

(b) by when these pending applications are likely to be cleared; and

(c) whether there is any scheme under Government's consideration to provide telephones to the applicants on the spot 'the same day', if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

As on 31.3.1989, the number of pending applications for new telephone connections of following cities in Gujarat are:

(i)	Ahmedabad	25558
(ii)	Baroda	17079
(iii)	Rajkot	3035
(iv)	Surat	27384

The present pending applications of these cities are likely to be cleared during the period 1990-95, subject to availability of resources.

There is no scheme to provide telephone to the applicants on the spot 'the same day'. However, under the scheme called 'Tatkal Scheme', whereby on payment of Rs. 30,000/- a telephone can be provided within 2 weeks time subject to feasibility of the telephone connection.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Mr. Chairman, Sir, the reply of the Minister is vague. The hon. Minister in his reply said, "the present pending applications of these cities are likely to be cleared during the period 1990-95, subject to availability of resources". But have you made any planning for all these four cities? How many telephones per year you are going to allot and how many new exchanges are going to be opened in Ahmedabad, Baroda, Rajkot and Surat?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : माननीय, यह प्रयास किया जा रहा है कि देश में जो टेलीफोन की मांग है, जो उसकी डिमांड है करीब 56 लाख की है और उसके विपरीत करीब 42 लाख टेलीफोन हमारे पास देश में है। गुजरात में भी करीब इनकी यही मात्र है। गुजरात के ये जो शहर है —अहमदाबाद बड़ौदा, राजकोट, सुरत में भी वही समस्या है कि जितनी मांग है, उतने टेलीफोन नहीं दे पा रहे हैं और वेटिंग लिस्ट काफी बड़ी है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा पूरे देश को देखते हुए कि जो मांग है, उसको हम कैसे पूरा करें। इसके लिए हम अगली योजना में बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं और योजना बन रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि जल्दी से जल्दी कैसे इसको करें।

श्री विठ्ठल भाई मोतीराम पटेल : माननीय सभापति जी, मैंने मंत्री जी से यह पूछा था कि कोई प्लानिंग है नए एक्सचेंज खोलने की और कितने कनेक्शन आप इन चार सिटीज में हर साल देने वाले हैं? दूसरा, यह जो तत्काल स्कीम आप की है 30,000 वाली, कि दो सप्ताह में आप कहते हैं, टेलीफोन मिल जाएगा। पहले ओ० वाई० टी० टेलीफोन से शुरु किया, तब ओ०

वाई० टी० में भी यही कहा गया था कि आप ओ० वाई० टी० में रजिस्टर करवाइए आप को जल्दी टेलीफोन मिल जाएगा? अब ओ० वाई० टी० में भी काफी एप्लीकेशन टेलीफोन के लिए पेंडिंग पड़ी है। तो आप की पूरी प्लानिंग क्या है और इनको कब तक टेलीफोन मिल जाएगा? जो आप को यह तत्काल स्कीम है, उसके रेण्ट पर, कोई फक है या वही सबका का सेम है?

श्री वीर बहादुर सिंह: मान्यवर,, जैसा मैंने कहा कि योजना तो बनाई जा रही है और खास तौर से आठवीं पंचवर्षीय योजना में काफी काम करने का प्रयास किया जा रहा है। यह हम योजना के लिए प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो मांग है, उसको कैसे पूरा करें। हमारा यह प्रयास है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के अंत तक ज्यादा से ज्यादा जो मांग है, उसको हम कोशिश करेंगे कि पूरा करें। जहां तक तत्काल सेवा की बात है यह तत्काल सेवा में 30,000/- रुपये जमा करने के दो सप्ताह के अंदर हम टेलीफोन दे देते हैं अगर टेलीफोन वहां पर देना संभव है, तो यह व्यवस्था उसमें है।

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Sir, generally, a letter is received from the Ministry that your telephone connection has been sanctioned. But when we inquire at the divisional level, they say, no, you will not get a telephone. Have these facts been brought to the notice of the Ministry and if we bring these facts to the notice of the Ministry, what action the Ministry will take?

श्री वीर बहादुर सिंह: मान्यवर, जहां कहीं भी कोई टेलीफोन सेंक्सन किया जाता है और हमारे पास कोई सूचना आती है कि सेंक्सन हो गया; लेकिन टेलीफोन नहीं लग पाया, यह भी हो सकता है उस एरिए में टेलीफोन कनेक्शन की लाइनें न हों, जब नई लाइनें डाली जाती है तो उनको प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद और लोगों को दिए जाते हैं।

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Six months? No telephone for months after getting the sanction?

श्री सभापति: सेंक्शन कर दिए और पता नहीं कि क्या दिक्कतें हैं ...

श्री शान्ति त्यागी: सभापति जी, हमारे संचार मंत्री जी का ग्रामीण भागों से लगाव है और इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कालेज हैं, बड़ अस्पताल हैं, सरकारी या प्राइवेट और बड़ केन्द्र हैं, न्याय पंचायतें हैं, ब्लाक डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर हैं, क्या उन जगह पर आपने टेलीफोन देने की कोई योजना बनाई है मैं पूरे देश की जब बात कर रहा हूं जिसमें गुजरात भी शामिल है। अगर आपने योजना नहीं बनाई है तो क्यों नहीं?

श्री वीर बहादुर सिंह: श्रीमन, यह प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षत्र या जो बड़े टाउन हैं, ब्लॉक स्कूल कालेज हैं, बड़े सेंटर हैं, उनको प्राथमिकता देकर टेलीफोन लगाए जाएं। जहां तक हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं उनको देखते हुए हम कार्य करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, बुनियादी सवाल यह है कि टेलीफोन जरूरतमंद को मिलना चाहिए या उसको जिसके पास पैसा है? मंत्रालय ने एक योजना शुरू की है तत्काल टेलीफोन की। मगर शर्त यह है कि 3 हजार रुपया नगद जमा कराओ। अगर 30 हजार रुपये नहीं हैं और जरूरत है तो तत्काल सेवा से वंचित होंगे। मंत्री महोदय किस कसौटी पर इस फैसले को सही साबित करते हैं?

श्री वीरबहादुर सिंह : मान्यवर, विभाग के लिए साधनों की भी आवश्यकता होती है और कभी-कभी इसके अभाव में हम काम नहीं कर पाते हैं जब हमलोग रजिस्टर करते हैं तो उसमें दो कैटेगरीज है, उसके बाद तीसरी कैटेगरी है इस तरह के लोगों को जो पैसे वाले हैं, अगर वह पैसा जमा करे तो उनके लिए जो पैसा खर्च होता है पूरा पैसा खर्च करके टेलीफोन लगा देते हैं । लेकिन जब रिसोर्सेज नहीं है तो जितना हम चाहते हैं वहां तक भी नहीं कर पाते हैं ।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Mr. Chairman, Sir, even though the question was about Ahmedabad, Baroda or Surat, the Minister has extended the answer in generality. The question relates to new connections. I am worried about the telephones which are on my table. They are not working three days in a month, sometimes eight days in a month. There is no technical staff at the exchanges. Has the Minister noticed these defects in the working of telephones? Has he got any plan to see that telephones work properly and the calls are billed properly instead of double-billing as is being done now. As you are aware, every M.P. is complaining of over-billing. Has the Ministry got any plan to see that telephones work all the thirty or thirty-one days in a month, throughout the year?

SHRI LAL K. ADVANI: Will refund be made for the days on which the telephone is not working?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: There is a provision in the agreement that telephone subscribers can use the department if the telephone is not working, for refund. Will the Government drive the subscribers to Court or will it improve the functioning of the department?

SHRI M. A. BABY: Sir, the condition is like telephones. There is no reply.

श्री वीर बहादुर सिंह : मान्यवर, जो टेलीफोन खराब होते हैं उनको ठीक करते जाते हैं और वास्तव में जो हमारा मोशन है बैटर कम्यूनिकेशन का, इसमें हमने काफी सुधार किए हैं। जहां टेलीफोन खराब थे उनको बदल दिए हैं, जहां केवल खराब थे वहां केवल बदल दिए हैं, जहां फॉल्ट थे वहां वे ठीक किए गए हैं । यह प्रयास किया जा रहा है कि वे ठीक से काम करें ।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं दो बिन्दुओं पर । पहला तो यह है कि जितने एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए कोई सालाना योजना बनाई गयी है कि इस साल में इतने लगेंगे, नेक्स्ट इयर में इतने लगेंगे ?

श्री सभापति : आप प्रश्न से बाहर ज्यादा न जाइए । यह सिर्फ चार नगरों के बारे में है ।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं उसी के बारे में कह रहा हूं । आपने एलाऊ कर दिया है मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। क्या कोई एनुअल तारगेट है कि डेट आफ एप्लीकेशन से इतने साल के अंदर दे दिया जाएगा ? दूसरे यह कि जिनको दिया जाता है क्या इस बारे में यह देखा गया है कि कॉल मैटरलाइज करने में जितना पैसा लगता है उससे ज्यादा नान मैटरलाइज करने में लग जाता है तो क्या इसकी कोई गारन्टी आप दे सकते हैं जिससे लोगों का बचाव हो सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह : यह तो सही है कि टारगेट हर साल का रखा जाता है कि कितने टेलीफोन लगाये जायेंगे । इस साल का टारगेट हमारा चार लाख से ज्यादा टेलीफोन लगाने का है । लेकिन वेटिंग लिस्ट जो इस वक्त देश में है वह 14.2 लाख की है । इस साल हम चार लाख से ज्यादा लगायेंगे तो वेटिंग लिस्ट उसी हिसाब से और बढ़ जाएगी । यह हमारा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा टेलीफोन लगाये जायें । जो डिमांड है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ।